

1. केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने को मिली मंजूरी : केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा— योजना के बुनियादी ढांचे और सेवा वितरण का होगा पुनर्गठन।
2. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना-2026 पारित : परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा— योजना के माध्यम से प्रदेश के हर गांव तक पहुंचेगी बस सेवा।
3. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 12 मार्च को दो दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे लखनऊ : 13 मार्च को मुख्यमंत्री के साथ करेंगे ग्रीन कॉरिडोर का उद्घाटन।

और

4. प्रयागराज, मेरठ और अयोध्या समेत आसपास के जनपदों में आज छाया रहा कोहरा : मौसम विभाग के मुताबिक अगल चार-पांच दिनों तक बनी रहेगी धुंध की स्थिति।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में बताया कि जल

जीवन मिशन के पुनर्गठन के लिए मंत्रिमंडल ने इसके कुल परिव्यय को बढ़ाकर 8 लाख 69 हजार करोड़ रुपये कर दिया है। इसमें केंद्र सरकार की ओर से 3 लाख 59 हजार करोड़ रुपये की सहायता शामिल है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन को बुनियादी ढांचे के निर्माण से लेकर सेवा वितरणके स्तर तक पुनर्गठित किया जाएगा।
बाइट.....

जल जीवन मिशन का आज 2.0 वर्जन अप्रूव हुआ। 1.0 वर्जन करीब 13 करोड़ परिवारों तक पहुंचा नल से जल। अब इन सारे प्रोजेक्ट की आपरेशन एण्ड मेन्टीनेन्स, वाटर सोर्स, सोसाइटी को जितनी डिफरेंट जो कमेटीज बनी है विलेज की कमेटी, ग्राम सभा की कमेटी, पंचायत की कमेटी इन सबको इनवाल्व करना। फिर जहां पर पॉपुलेशन बढ़ रही है, वहां पर नए सोर्स निकालना एक तरीके से अब इसको सस्टेनेबल बनाने का टाइम आया। शुरू में टेक ऑफ करना, कवरेज लाना अब है इसको सस्टेनेबल बनाना।

मंत्रिमंडल ने एक समान राष्ट्रीय डिजिटल ढांचा, सुजलम भारत, स्थापित करने को भी मंजूरी दी है। इसके तहत प्रत्येक गांव को एक विशिष्ट सुजल गांव या सेवा क्षेत्र आईडी आवंटित की जाएगी। इससे स्रोत से नल तक संपूर्ण पेयजल आपूर्ति प्रणाली का डिजिटल मानचित्रण किया जाएगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह ने बताया कि कैबिनेट ने

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना-2026 को स्वीकृति दे दी है। इस योजना के माध्यम से अब उत्तर प्रदेश के हर गांव तक बस पहुंचेगी। योजना के तहत निजी बसें चलाने की अनुमति दी जाएगी। इन बसों को परमिट और टैक्स से मुक्त रखा गया है। बाइट.....

हम लोग यह नई पॉलिसी लाए हैं कि उत्तर प्रदेश के उनसठ हजार एक सौ तिरसठ गांवों में बस जाए सभी गांवों में। इसकी विशेषता यह होगी कि एक तो पहले यह टैक्स फ्री होगा। प्राइवेट लोगों को हम इसको चलाने की अनुमति देंगे। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी। उस कमेटी में एस. पी., सी.डी.ओ. और हमारे ए.आर.टी.ओ. और हमारे आर.एम. जो होते हैं हमारे लोकल लेवल पर, ये इसके मेम्बर होंगे।

परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह ने बताया कि सरकार ने यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के मद्देनजर अब ओला उबर जैसी टैक्सी का पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया है। बैठक में स्टाम्प और पंजीयन विभाग के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत अब प्रापर्टी बेचने वाले की पहचान को खतौनी में देखा जाएगा। विभाग के राज्य मंत्री रविन्द्र जायसवाल ने बताया कि स्टाम्प निबंधन विभाग अब रजिस्ट्री से पहले मालिकाना हक की जांच करगा। बाइट.....

अभी तक उत्तर प्रदेश के अंदर जब भी कोई आप रजिस्ट्री कराते हैं तो रजिस्ट्रार केवल देखता था कि क्रेता-विक्रेता दो चीजें खरीद-बिक्री कर रहे हैं, उसका स्टाम्प मिलना चाहिए। स्टाम्प विभाग को मलकाना चेक करने का व्यवस्था नहीं था कि बेचने वाला व्यक्ति अधिकृत मालिक है कि मालिक नहीं है। अब आज के बाद से यह हो जाएगा कि जब कोई प्रापर्टी बेचने आएगा तो उनकी खतौनी में या अन्य दस्तावेज में उसमें उसका नाम है कि नहीं

बेचने वाले का। अगर बेचने वाले का नाम नहीं है तो वह रजिस्ट्रार उसको रोकेंगा

कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 1975 में संशोधन, बांदा में 20 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता के नए डेयरी प्लांट की स्थापना के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी। इसके अलावा अयोध्या में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 12 मार्च को दो दिवसीय दौरे पर लखनऊ आएंगे। दौरे के दूसरे दिन 13 मार्च को रक्षा मंत्री समतामूलक चौराहे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ग्रीन कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। साथ ही कर्मचारियों को सम्मानित भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने बताया कि इसी दिन रक्षा मंत्री हसनगंज स्थित झूलेलाल वाटिका में आयोजित जनसभा को भी संबोधित करेंगे।

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज मथुरा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के 15वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने 177 छात्रों को डिग्रियां प्रदान कीं। राज्यपाल ने मेधावी छात्रों को 14 स्वर्ण, चार रजत व दो कांस्य पदक देकर

सम्मानित किया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार के पशुपालन आयुक्त डॉ नवीन बी. महेश्वरप्पा उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने छात्रों से पढ़ाई पर पूरा ध्यान केंद्रित करने और देश के विकास में योगदान देने के लिए प्रेरित किया।

ब्रेक

यह समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिये आप हमारी वेबसाइट न्यूज़ ऑन ए0आई0आर0 डॉट जी0ओ0वी0 डॉट आई0एन0 पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रतिनिधिमंडल ने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर भारत सरकार की ओर से जारी एयरोड्रोम लाइसेंस प्रस्तुत किया। इस लाइसेंस के मिलने के बाद अब एयरपोर्ट के उद्घाटन और वाणिज्यिक उड़ानों की शुरुआत की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। पेश है एक रिपोर्ट.....

एयरपोर्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रिस्टोफ़शनेलमैन समेत वरिष्ठ अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को मुलाकात के दौरान परियोजना की प्रगति और आगामी चरणों की जानकारी भी दी। गौतमबुद्ध नगर के जेवर

में विकसित हो रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को देश और दुनिया के प्रमुख शहरों से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है। एयरपोर्ट का विकास चार चरणों में किया जा रहा है। पहले चरण में एक रनवे और एक यात्री टर्मिनल भवन बनाया गया है, जिसकी क्षमता प्रतिवर्ष लगभग 1 करोड़ 20 लाख यात्रियों की होगी। दूसरे चरण में क्षमता बढ़ाकर 3 करोड़ यात्रियों तक पहुंचाई जाएगी। तीसरे और चौथे चरण में विस्तार के बाद कुल क्षमता 7 करोड़ यात्रियों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। समाचार कक्ष से समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 14 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत के प्रचार प्रसार के लिए अमरोहा में आज जनपद न्यायाधीश विवेक ने न्यायालय परिसर से प्रचार वाहन और जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जनपद न्यायाधीश ने लोगों से अपील की कि वे लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ लेकर वादों का निस्तारण कराएं। बाइट.....

राष्ट्रीय लोक अदालत के अंतर्गत सभी प्रकार के दीवानी प्रकृति के वाद, मोटर दुर्घटना के वाद, पारिवारिक न्यायालयों से संबंधित पारिवारिक वाद, समनीय मामले जो आपराधिक प्रकृति के हैं उनमें पक्षकार अपना चेक बाउन्स के वाद भी इसमें आ सकते हैं। जितने भी तरह के मामलों में सुलह समझौता संभव होता है। हमारी सबसे यही अपील रहती है कि वह न्यायालय में आकर अपने अधिवक्ता के माध्यम से यह जानकारी भी करें कि क्या उनके मामले ऐसे हैं जो सुलह समझौता हो सकते हैं। कोई भी श्रेणी हो जिसको लगता हो कि हम चाहते हैं उनके मामलों को निस्तारित किया जाए।

पश्चिम एशिया में मौजूदा स्थिति को देखते हुए सरकार ने प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए प्राकृतिक गैस के उत्पादन को विनियमित करने आपूर्ति बनाए रखने समान वितरण और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लागू किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार घरेलू पाइपलाइन प्राकृतिक गैस आपूर्ति परिवहन के लिए सीएनजी, एलपीजी उत्पादन पाइपलाइन कंप्रेसर ईंधन और अन्य आवश्यक पाइपलाइन परिचालन आवश्यकता वाले क्षेत्रों को प्राकृतिक गैसकी आपूर्ति में प्राथमिकता दी गई है। आदेश में कहा गया है कि उर्वरक संयंत्रों को पिछले छह महीनों की औसत गैस खपत के 70 प्रतिशत के बराबर प्राकृतिक गैस की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।

प्रयागराज, मेरठ, मुरादाबाद, मुज़फ्फरनगर, सहारनपुर, अयोध्या समेत आसापास के जनपदों में आज कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 4-5 दिनों तक इन क्षेत्रों में धुन्ध की परिस्थितियाँ बनी रहने की आशंका है। इसके बाद 15 मार्च से प्रदेश के तराई इलाकों के साथ-साथ पूर्वांचल के कुछ भागों में वर्षा होने के साथ-साथ तापमान में थोड़ी गिरावट आने का अनुमान है।

(समाप्त)